(d) The investment of Rs. 383.50 crores is for ongoing and new projects during the current year only.

(e) The production during the current year is expected to go up to 113.50 million tonnes. Investment programme for the next year has not yet been formulated.

(f) The demand of coal during 1980-81 is estimated at 119.80 million tonnes against tentative production programme of 113.50 million tonnes which is under revision.

Regulation of Excess Production in Drug Industry

2509. SHRI SURYA NARAIN SINGH: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether Government propose to regularies excess production in the drug industry;

(b) if so, the details; and

(c) whether this move is inconsistent with the recommendation of the Hathi Committee report on drug industry?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) Yes Sir.

(b) Details in this regard are indicated in paragraphs 27 to 36 of the Statement (laid on the Table of Lok Sabha on 29th March, 1978 by the then Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers) containing Government's decisions on the Report of the (Hathi) Committee on Drugs & Pharmaceutical Industry.

(c) Government's comprehensive decisions on regularisation of excess production are based on, and are, by and large, in accord with the Hathi Committee's recommendations.

डीजल की खपत

2510. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में डीजल की खपत कितनी है ; और

(ख) निकट भविष्य में डीजल और मिट्टी के तेल उत्पादन में वृद्धि की संभावनाएं क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान देश में, हाई स्पीड डीजल की कुल खपत करीब 9.73 मि० मी० टन थी ।

(ख) इस समय असम से मिलने वाले तेल पर काम करने वाली शोधनशालायें पूर्ण रूप से बन्द रहने या रुक-रुक कर काम करने के कारण हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल दोनों की स्वदेशी उपलब्धता में गिरावट आई है । इस कमी को इन दो उत्पादों के आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है जोकि पिछले कुछ महीनों में अधिकतम किया गया है ताकि तटीय स्थानों पर इनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो। देश के ऊपरी भागों के स्थानों पर इन उत्पादों की उपलब्धता परिवहन क्षमता पर निर्भर है। डीजल और मिट्टी के तेल की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि तभी सम्भव होगी जब 6 मि० मी० टन क्षमता वाली मथुरा शोधनशाला में उत्पादन आरम्भ हो जाएगा और अगले एक वर्ष के दौरान बोंगई गांव शोधनशाला अपनी 1 मि०मी० टन की पूर्ण क्षमता पहुंच जाऐगी ।

माही नदी पर कडाना बांध का निर्माण करने के लिये गुजरात और राजस्थान के बीच करार

2511. **श्री बोलत राम सारण** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नदी पर उच्चस्तरीय टैंक का निर्माण पूरा होने तक राजस्थान के जालौर और बाड़मेर के शुष्क क्षेत्रों तथा गुजरात के जिला खेरा में सिंचाई के लिये पानी का उपयोग करने हेतु 419 फुट की ऊंचाई का माही नदी में कडाना बांध और 931 फुट के स्तर पर बांसवाड़ा में बजाज सागर बांध का निर्माण करने के लिये गुजरात और राजस्थान की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि योजना आयोग ने इन दो राज्य सरकारों के बीच हुए इस समझौते के बाद ही परियोजना की स्वीकृति दी थी ; और